

भारत की सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसरो निभा रहा अहम भूमिका, 10 सैटेलाइट कर रहे हैं काम

नयी दिल्ली २१/११ (संवाददाता): भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ है मगर ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भारत की सरहदों की सुरक्षा करने के लिए सेना के जवान लगातार सरहद पर पहरा दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जी नारायणन ने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।

उन्होंने बताया कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के रणनीतिक उद्देश्य से कम से कम 10 सैटेलाइट लगातार चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। इस्फाल में कल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख

ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठन के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

इसरो अध्यक्ष ने कहा, देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के रणनीतिक उद्देश्य से कम से कम 10 उपग्रह लगातार चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। वी नारायणन ने कहा, आप सभी हमारे पड़ोसियों के बारे में जानते हैं। अगर हमें अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो हमें अपने उपग्रहों के माध्यम से सेवा करनी होगी। हमें अपने 7,000 किलोमीटर के समुद्री तट क्षेत्रों की निगरानी करनी होगी। हमें पूरे उज्जरी भाग पर लगातार नजर रखनी होगी। उपग्रह और ड्रोन तकनीक के बिना, हम यह हासिल नहीं कर सकते।

सेना ने कहा कि पिछले

कुछ दिनों से उज्जरी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के इलाकों में रात के समय मची अराजकता और झड़पों के बाद, 11 और 12 मई की मध्य रात्रि में क्षेत्र में काफी हद तक शांति बनी रही। सेना के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य क्षेत्र शांत हैं तथा युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन की कोई घटना सामने नहीं आई है।

सेना ने कहा कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के जवाब में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी, भारी गोलाबारी और ड्रोन हमलों के बाद हाल के दिनों में यह पहली शांत रात थी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध में शुरू किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और



पाकिस्तान के कच्चे वाले कश्मीर (पीओके) में प्रमुख आतंकवादी स्थलों को नष्ट कर दिया गया था।

पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी और ड्रोन हमलों की कोशिशें देखी गईं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में शांति को बाधित करना था। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों को भारतीय वायु

रक्षा प्रणाली द्वारा काफी हद तक बेअसर कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर 11 हवाई ठिकानों को नष्ट करने की पुष्टि की और उनकी सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया।

रविवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेजिटिमेंट जनरल राजीव घई (सैन्य संचालन महानिदेशक), वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद (नौसेना संचालन महानिदेशक) और एयर मार्शल ए के भारती (वायु संचालन

महानिदेशक) ने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के प्रमुख परिणामों का खुलासा किया। लेजिटिमेंट जनरल राजीव घई ने अपने समकक्ष के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पड़ोसी देशों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। उन्होंने कहा कि शत्रुता समाप्त होने के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तानी सेना ने

इन सहमतियों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के डीजीएमओ ही थे जिन्होंने शत्रुता समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था।

घई ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, मेरा पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ संवाद कल 15:35 बजे हुआ और इसके परिणामस्वरूप 10 मई को 17:00 बजे से दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई, जब उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम शत्रुता समाप्त करें।

हमने 12 मई को 12:00 बजे आगे की बातचीत करने का भी निर्णय लिया है, ताकि इस समझ को दीर्घावधि तक बनाए रखने के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा

कि दोनों डीजीएमओ के बीच हुए समझौते के उल्लंघन का भारत ने कड़ा जवाब दिया। घई ने कहा, हालांकि, निराशाजनक रूप से, जैसा कि अपेक्षित था, पाकिस्तानी सेना को सीमा पार और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलीबारी करके इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में केवल कुछ घंटे लगे, इसके बाद कल रात और आज तड़के ड्रोन घुसपैठ की गई। इन उल्लंघनों का कड़ा जवाब दिया गया।

भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कच्चे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब था।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय वीरों को हाथ जोड़कर नमन, ये हैं तभी हम है... जय हिंद, जय भारत

नयी दिल्ली २१/११ (संवाददाता): भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया हो लेकिन अभी भी भारतीय सेना पूरी तौर से चौकसी हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोगला है। वह अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी के साथ कहा गया है कि अगर फिर से कोई नापाक हरकत की गयी तो सीधा युद्ध होगा। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अपने सोशल मीडिया से दी थी। भारतीय वीर कैसे बॉर्डर पर पाकिस्तान की कोशिशों को ध्वस्त कर रहे थे अपने जान की परवाह किए बिना, यह भारत की सेना और सुरक्षा बल की ताकल को दर्शाता है। इस दौरान कुछ भारतीय सेना के और भारतीय सुरक्षा बल के सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्योछावर कर दिया। आइए उन्हें याद करते हैं- जम्मू कश्मीर में आरएस पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलीबारी के दौरान शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के

उपनिरीक्षक मोहज्जम इज्तियाज का पार्थिव शरीर सोमवार को पटना लाया गया। इस दौरान शहीद के बेटे इमरान रजा हवाई अड्डे पर चुपचाप खड़े रहे। उपनिरीक्षक मोहज्जम इज्तियाज जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात थे। इमरान रजा ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, “मुझे अपने पिता पर गर्व है और मैं उन सभी को सलाम करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।” उन्होंने कहा, “मेरे पिता बहुत मजबूत व्यक्ति थे। मैंने उनसे आखिरी बार 10 मई (शनिवार) को सुबह साढ़े पांच बजे बात की थी। उनके दाहिने पैर में चोट लगी थी। घायल होने के बाद उपनिरीक्षक इज्तियाज उसी शाम शहीद हो गए थे। सुरक्षाकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर एवं हवाई अड्डे पर पुष्पांजलि अर्पित किए जाने के बाद इज्तियाज के पार्थिव शरीर को सारण जिले के नारायणपुर गांव स्थित उनके घर ले जाया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इज्तियाज का पार्थिव शरीर लेने

के लिए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कई मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। इमरान ने भारत में आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को उचित सबक सिखाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान को उचित सबक सिखाना चाहिए। हमारी सरकार को ऐसा करारा जवाब देना चाहिए कि किसी बेटे को कभी अपने पिता को न खोना पड़े।” हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए यादव ने कहा, “जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इज्तियाज शहीद हो गए। उनके जैसे बहादुर लोगों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा।” राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, “मोहज्जम इज्तियाज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया... हमारे बहादुर सैनिकों ने उनके बलिदान का बदला ले लिया

है।

पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए झुझुनू जिले के जवान सुरेंद्र कुमार का रविवार को उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। पाकिस्तान की ओर से हुए हमले में भारतीय वायुसेना के असिस्टेंट मेडिकल साजेंट सुरेंद्र कुमार शनिवार को उधमपुर हवाई अड्डे पर शहीद हो गए थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर दिल्ली से सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव मंडावा पहुंचा। इसके बाद तिरंगा यात्रा शुरू हुई और जवान का पार्थिव शरीर मेहरादासी गांव में उनके घर पहुंचा। गांव में उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुरेंद्र कुमार के आठ साल के बेटे दक्ष ने अपने पिता को मुखातिब दी। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जिन्होंने भारत माता की जय और सुरेंद्र कुमार अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़,

अविनाश गहलोत व झाबर सिंह खर्ग, सांसद मदन राठौड़ सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे।

पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के एक अधिकारी का रविवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा राजौरी के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राज कुमार थापा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शनिवार सुबह राजौरी में थापा के आवासीय परिसर में मोर्चर गोले गिरने से उनकी मौत हो गयी थी। उनके पार्थिव शरीर को पुलिस वाहन में जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित उनके रूप नगर स्थित निवास पर लाया गया और बाद में उनका अंतिम संस्कार पास के श्मशान घाट में किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के

लिए अथक परिश्रम करने वाले इन सज्जानित लोकसेवक को श्रद्धांजलि दी। सिन्हा ने कहा, “डॉ. थापा का जम्मू-कश्मीर के विकास में विपुल योगदान है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ।”

आंध्र प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से गोलाबारी के दौरान शहीद हुए सैनिक एम. मुरली नाइक के परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की रविवार को घोषणा की। शनिवार रात को मुरली नाइक का पार्थिव शरीर श्री सत्यसाई जिले स्थित उनके घर लाया गया, जिसके बाद रविवार को उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण उनके घर पहुंचे और शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी ओर से 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की और परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की। कल्याण ने संवाददाताओं से कहा, ऋमुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मुरली नाइक के परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह

राशि, पांच एकड़ कृषि भूमि, आवास के लिए 300 वर्ग गज जमीन देने की घोषणा की है। कैबिनेट की चर्चा के बाद नाइक के परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री नारा लोकेश और अन्य मंत्रियों ने नाइक के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके शोकाकुल माता-पिता को ढाँढस बंधाया। लोकेश ने कहा, राज्य नाइक की बहादुरी के सम्मान में नतमस्तक है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि नाइक का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

गोलीबारी में गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद शहीद हुए एक युवा सैनिक सुनील कुमार को यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास उसके गांव में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई दी गई। ‘4-एकेएलआई (जम्मू-कश्मीर लाइट इंफैंट्री रेजिमेंट)’ में तैनात राइफलमैन सुनील कुमार (25)

शनिवार तड़के आरएस पुरा सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलाबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में

उन्होंने दम तोड़ दिया। सुनील कुमार एक सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके दो बड़े भाई सशस्त्र बलों में सेवारत हैं जबकि पिता पूर्व सैनिक हैं। सुनील कुमार के रिश्तेदारों ने कहा कि वह बचपन से ही सेना में शामिल होने और देश की सेवा करने के सपने देखता था। अरनिया सेज्जत में सुनील कुमार के त्रिवा गांव के अधिकतर निवासियों को आठ मई को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। दरअसल एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास अग्रिम गांवों को अंधाधुंध तरीके से निशाना बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें दागी थीं।

हालांकि, जब तिरगे में लिपटे ताबूत में वीर जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर एक सुसज्जित सैन्य वाहन में रखकर उनके गांव लाया गया, तो सैकड़ों शोक संतप्त लोग उन्हें अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हो गए। सुनील कुमार के बलिदान और राष्ट्र की प्रशंसा में नारे लगाये जा रहे थे।

कच्छ में ड्रोन देखे गए, फिर से ज़्लैकआउट किया गया-गृह राज्य मंत्री सांघवी

नयी दिल्ली २१/११ (संवाददाता): गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ में कई ड्रोन देखे जाने के बाद शनिवार देर शाम जिले में पूर्ण ‘ज़्लैकआउट’ लागू कर दिया गया। यह घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोकें जाने को लेकर हुए समझौते के कुछ घंटे बाद हुआ।

गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने ‘एक्स’ पर घोषणा की, “कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं।

अब पूर्ण ज़्लैकआउट लागू किया जाएगा। कृपया सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं।” कच्छ और पाटन जिले के कुछ हिस्सों में आधिकारिक तौर पर ‘ज़्लैकआउट’ की घोषणा कर दी गई, जबकि पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन



किए जाने की खबरों के बाद लोगों ने देवभूमि द्वारका (पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित जिले) के कुछ हिस्सों में ‘ज़्लैकआउट’ का पालन करने का निर्णय लिया। कच्छ के जिलाधिकारी आनंद पटेल ने कहा, “संपूर्ण कच्छ जिले में तत्काल प्रभाव से ज़्लैकआउट घोषित कर दिया गया है तथा सभी नागरिकों से इसका सज्जी से पालन करने

को कहा गया है। पाटन जिले के जिलाधिकारी तुषार भट्ट ने बताया कि जिला प्रशासन ने संतालपुर तालुका के गांवों में भी ज़्लैकआउट लागू कर दिया है।

उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि जामनगर में भी ‘ज़्लैकआउट’ लागू कर दिया गया है।

नयी दिल्ली २१/११ (संवाददाता): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता की पेशकश कर विवाद खड़ा कर दिया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिञ्चल ने ट्रंप के हालिया बयान की आलोचना की और मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। सिञ्चल ने कहा कि ट्रंप के बयान से कई सवाल उठेंगे और विपक्ष को इस मुद्दे पर गलत जानकारी दी गई।

कपिल सिञ्चल ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, %इस टवीट पर भी कई सवाल उठेंगे... तो ज़्याा हुआ (भारत-पाकिस्तान समझौते के बारे में), कैसे और ज्यों, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है... इसलिए हम आज



कोई आलोचना नहीं करेंगे। हम केवल एक विशेष संसद सत्र और एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक सरकार उन्हें आश्वासन नहीं देती कि प्रधानमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे, तब तक वे बैठक में शामिल न हों... मुझे पूरा भरोसा है कि अगर डॉ. मनमोहन सिंह

आज प्रधानमंत्री होते, तो वे सर्वदलीय बैठक में मौजूद होते और एक विशेष सत्र भी बुलाया जाता। इससे पहले, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को कहा कि यह मुद्दा बाइबिल में वर्णित 100 साल पुराना संघर्ष नहीं है, बल्कि यह केवल 78 साल पहले शुरू हुआ था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, %अमेरिकी प्रतिष्ठान में किसी

को अपने राष्ट्रपति ञ्चल्लञ्चर ञ्चदडुधञ्चभट्टुधसञ्जहद्वध को गंभीरता से शिक्षित करने की आवश्यकता है कि कश्मीर बाइबिल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है। यह 22 अक्टूबर, 1947-78 साल पहले शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के स्वतंत्र

राज्य पर आक्रमण किया था, जिसे बाद में 26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा %पूर्ण% रूप से भारत को सौंप दिया गया था, जिसमें अब तक पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कच्चाए गए क्षेत्र शामिल हैं। इस सरल तथ्य को समझना कितना मुश्किल है?

कलिंग समाचार

THE KALINGA SAMACHAR

(A Hindi Daily News Paper)

PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH

FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT

AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16

ROURKELA, PH. 0661-2646999

PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)

E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

कलिंग समाचार



संपादकीय

शनिवार 22 नवंबर 2025

सिख दंगा-राहुल की स्वीकारोक्ति

देश का मौजूदा दौर नेतृत्व द्वारा अपने उत्तरदायित्वों से बचने और दूसरों पर दोष मढ़ने का है। 2014 से प्रारंभ हुआ यह कालखंड ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है जिनमें नेतृत्व जि मेदारी से भागता नज़् आता है। भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं, उसमें चाहे खुद मोदी हों अथवा उनकी पार्टी या सरकार– हर तरह के उत्तरदायित्वों से पीछा छुड़ाती नज़् आती है। नोटबन्दी से लेकर किसान कानून हों जिनके कारण अनेक मौतें हुईं हों अथवा मणिपुर की त्रासदी, सुरक्षा में चूक के चलते पुलवामा की घटना हो या पिछले माह की पहलगाम की आतंकी घटनाएं– मोदी का किसी भी मामले में जि मेदारी लेना तो दूर, उनका कोई सादा सा बयान तक नहीं आता। जहां किसी प्रदेश के विधानसभा में पार्टी की चुनावी हार हो जाये तो स्टार प्रचारक होने के नाते ही सही– उन्हें अपनी भूमिका को ठीक से न निभाने के लिये न तो खेद प्रकट करते देखा गया और न ही हार का जि मेदार खुद को बताते पाया गया। निजी तौर पर उनकी गलत बयानी, सायास तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश करने की चालाकी सामने आने के बाद भी वे न तो अपनी चूक को स्वीकारेंगे, न ही ऐसी गलती दोहराने से बचने का संकल्प जतायेंगे। ऐसे दौर में राहुल गांधी 1984 के उन सिख दंगों की जि मेदारी सार्वजनिक रूप से लेते हैं, जब वे मात्र 14 साल के थे। उल्लेखनीय है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज़् इंदिरा गांधी के सिख सुरक्षार्कर्मियों ने जब इस फैसले के लिए उन्होंने गोलियों से भून दिया था, तब देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क उठे थे। खासकर, दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिखों का कत्ल हुआ था जिसका घाव अब भी भारत के सीने पर है और सिख स्वाभाविकतः आज भी उस घटनाक्रम से नाराज़् हैं। इन दंगों में अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की संलिप्तता पायी गयी। अनेक नेता दोषी भी पाये गये। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार उनमें बड़े नाम थे जिन्हें अति सुस्त ही सही, पर एक निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषी भी साबित किया गया है। बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ़ मुकदमे चलाये गये हैं। पिछले माह जब राहुल अमेरिका के दौरे पर गये थे, तब उन्होंने ब्राउन विश्वविद्यालय के वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में भाषण दिया था। एक सिख छात्र ने उनके पहले के एक भाषण का हवाला देते हुए कहा कि आप सिखों में डर पैदा करना चाहते हैं। याद हो कि राहुल ने विदेशी दौरे में ही एक भाषण में कहा था कि सिखों को कड़ा पहनने या केश धारण करने या गुरुद्वारे जाने से भी रोका जा सकता है। दरअसल राहुल का मतंव्य देश में अल्पसंं यकों की धार्मिक आजादी को भाजपा सरकार की ओर से खतरे से था। सिख युवक ने कहा कि, %वे (सिख) न केवल कड़ा धारण करना चाहते हैं, न केवल केश रखना चाहते हैं वरन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी चाहते हैं।% इसी सिलसिले में उस युवक ने जब सिखों के खिलाफ भड़के दंगों का मुद्दा उठाया तो राहुल ने साफगोई से कहा कि %वैसे वे उस दौरान नहीं थे, परन्तु वे दंगों पर उनकी पार्टी की गलतियों को अपने सिर पर लेने के लिये सहर्ष तैयार हैं।% इतना ही नहीं, उन्होंने कहा– %कांग्रेस द्वारा इतिहास में जो भी गलतियां की गयी हैं, उन सभी को वे जि मेदार लेते हैं।। यह वीडियो अब वायरल हुआ है, जिसमें सिखों के प्रति ही नहीं, वरन अल्पसंं यकों के प्रति भी राहुल का दृष्टिकोण तथा पार्टी की तत्स बन्धी गलतियों को लेकर उनकी स्वीकोरोक्ति जाहिर हुई है। युवक ने आरोप लगाया कि %आप भाजपा के नाम से सिखों को डरा रहे हैं जबकि आप कहते हैं कि राजनीति में निडरता होनी चाहिये। यदि ऐसा रहा तो पंजाब में भी भाजपा आ जायेगी। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं थी।% उक्त युवक की बात में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार आदि का भी उल्लेख था। उस युवक ने जब पूछा कि %क्या अतीत में उनकी पार्टी में परिपक्वता का अभाव था%, तो राहुल ने कहा कि %अतीत में कांग्रेस द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं, वे सभी की सहर्ष जि मेदारी लेते हैं।

राजेंद्र शर्मा

चुनाव के तीसरे चरण की ओर बढ़ते हुएए मोदी की भाजपा कुल मिलाकर बचाव की मुद्रा अपनाने पर मजबूर होती नजर आ रही है। यह उसके खुली सांप्रदायिक दुहाई का सहारा लेने के बावजूद है। उसके दुर्भाग्य से बचाव की यह मुद्रा भी काम आती नजर नहीं आ रही है। बेशकए अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ते हुएए उसने सीधे आरएसएस को भी प्रत्यक्ष रूप से मैदान में उतरने के लिए तैयार कर लिया है।

शुक्रवारए 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान नेए संघ.भाजपा की कुशंकाओं की और बाकी सब के इसके व्यापक अनुमानों की पुष्टिड्ड कर दी है कि जिस मोदी लहर का इतना ढोल पीटा जा रहा थाए वह तो खैर इस चुनाव में खोजे से भी नहीं मिलेगीए अलबत्ता इस बार मोदी उतार के काफी प्रबल लक्षण हैं। ये लक्षणए 4 जून को मोदी के सत्ता से उतरने तक ले जाएंगे या उससे कुछ पीछे रह जाएंगे या पहले ही रोक दिए जाएंगेए इसके लिए तो बेशक अभी सवा महीने और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिनए इस चुनाव में मोदी के उतार पर रहने के जो लक्षण पहले चरण में सामने आये थेए उनकी दूसरे चरण ने पुष्टिड्ड कर दी है। पहले चरण में अगए 2019 के चुनाव के मुकाबलेए 102 सीटों पर हुए मतदान में कुल मिलाकर 4 फ़ैसद वोट की गिरावट देखने को मिली थीए तो दूसरे चरण के मतदान में भी वही रझान बना रहा है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो वोट पड़े हैंए उनमें 2019 के चुनाव के मुकाबले 3 फ़ैसद से अधिक गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट से पहले चरण के बाद से लगाए जा रहे इस अनुमान की पुष्टिड्ड हो गयी है कि मतदान में यह गिरावटए कमो.बेश इस पूरे चुनाव की ही विशेषता रहने जा रही है। जाहिर है कि इस गिरावट के संकेत भीए पूरे चुनाव के लिए ही सच होने चाहिए।

दूसरे चरण की 88 सीटों में इस गिरावट में बेशकए केरल में हुई 6७5 की गिरावट भी शामिल है। लेकिनए इस राज्य की 20 सीटों पर मुकाबले से भाजपा को तो एक तरह से बाहर ही माना जा रहा है और इसलिए इसके रझान से भाजपा की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर इस चरण में मत फ़ैसद में यह गिरावट 13 राज्यों में से पूरे 11 में दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ही इसका अपवाद रहे हैं और कम से कम कर्नाटक का इस रझान का अपवाद रहना तोए किसी भी तरह से भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। कुछ ही महीने पहले जोरदार तरीके से कांग्रेस के शासन में आये कर्नाटक मेंए जहां 2019 में भाजपा 28 में से 26 सीटों पर काबिज हो गयी थीए मत फ़ैसद में बढ़ोतरी उसके संसदीय बोलबाले के छीझने का ही संकेत हो सकती है।

बहरहालए भाजपा के लिए इससे भी महत्वपूर्ण संकेतए उसका गढ़ मानी जाने वाली हिंदी पट्टी में मत फ़ैसद में बिहार में 3७5 फ़ैसदए मध्य प्रदेश में 9७1 फ़ैसदए उत्तर प्रदेश में 7 फ़ैसदए राजस्थान में 3७4 फ़ैसद की गिरावट होना है। पहले चरण में भी दर्ज हुई इस गिरावट का दूसरे चरण में भी जारी रहनाए इसका स्पष्टड्ड संकेत है कि 2019 के चुनाव मेंए सबसे बढ़कर पुलवामा और बालाकोट के सहारेए राष्ट्रवाद के जिस आ ड्डुमान के बल पर उठाई गई लहर के ज्वार ने भाजपा को तीन सौ पार पहुंचाया थाए वह ज्वार कब का उतर कर भाटा बन चुका है और इस बार पूरे चुनाव में भाटा ही बना रहने जा रहा है।

यह वही हिंदी पटड्डुटी है जहां विपक्ष के नाम पर कांग्रेस को मप्र तथा बिहार में एक.एक सीट और उत्तर प्रदेश में सपा.बसपा का एका होने के बाद भीए उसे 15 तथा कांग्रेस को एक सीट ही मिल पाई थी। उसी हिंदी पट्टी में

मतदान में उल्लेखनीय गिरावटए तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के प्रति मतदाताओं की उदासीनता से लेकर विमुखता तक का खुला ऐलान कर रही है।

जैसा कि अधिकांश राजनीतिक प्रेक्षकों ने दर्ज कियाए पहले चरण के मतदान के संकेतों से हुई घबराहट का नतीजाए खुद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के अपनी प्रचार कार्यनीति में साफसाफ दिखाई देने वाला बदलाव करए खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक अपील को प्रचार केंद्र में लाने के रूप में सामने आया। ड़्क्षहदीभाषी पट्टी में ही राजस्थान मेंए बांसवाड़ा के अपने कु ड्डयात भाषण से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरूआत कीए जिसमें कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र तथा उसके तत्कालीन प्रधानमंत्रीए मनमोहन सिंह के 2006 के एक भाषण का नाम लेकरए विपक्ष पर गरीब दलितोंए आदिवासियोंए पिछड़ों की संपत्तियांए विशेष रूप से महिलाओं का सोना तथा मंगलसूत्र तक जब्त करने के मंसूवे बनाने का ही आरोप नहीं लगाया गयाए नाम लेकर यह आरोप भी लगाया गया कि वे ये संपत्तियां छीनकर मुसलमानों में यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों मेंए घुसपैठियों में बांटेंगी! इस सरासर झूठे दावे और खुली सांप्रदायिक अपील के खिलाफ कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी पार्टियों और हजारों आम नागरिकों के भी चुनाव आयोग से शिकायत करने से लेकरए पुलिस से शिकायत करने तक के बावजूदए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के बीच के दौर में अपने चुनावी भाषणों में इसी को अपना मु ड्ड्य राग बनाए रखा है। हां! उन्होंने इतना जरूर किया कि बाद में मुसलमान शब्द का प्रयोग न करने की सावधानी बरतनी शुरू कर दी और उसकी एवज में तुष्टीकरण के लाभार्थी की संज्ञा का सहारा लेना शुरू कर दिया। बाद में चुनाव आयोग के एक अनोखे फैसले मेंए इन भाषणों पर शिकायतों के

के कम से कम चार प्रत्याशियों के संविधान बदलने के लिए चार सौ जरूरी होने के अलग.अलग दावों सेए कमजोर तबकों की इसकी आशंकाओं को बल मिला है कि चार सौ पार के पीछे मंशाए संविधान को ही बदल देने और आरक्षण को खत्म करने की है। इस जोर पकड़ती धारणा से पीछा छुड़ाने की कोशिश में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ आरक्षण की चोरी के आरोपों का स्वर ही तेज नहीं कर दिया हैए वे बार.बार इसका भरोसा दिला रहे हैं कि खुद संविधान को बदलना तो दूरए जिसमें आरक्षण भी शामिल हैए वे तो किसी और को बदलने भी नहीं देंगे। अमित शाह ने मोदी की ओर इसकी मोदी गारंटी देनी शुरू कर दी है। घबराहट इतनी ज्यादा है कि मोदी की सभाओं में चार सौ पार का जिक्र तक गायब हो गया है। इतना ही नहींए अब तो फ़िर एक बार मोदी सरकार जैसे सीधे नारों से भी बचा जा रहा है और महाराष्ट्र में हाल की अपनी चुनाव सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी गरीबों की सरकारए दलितों की सरकारए पिछड़ों की सरकार के नारे लगवाते नजर आए! इस बीच विकसित भारत के नारेए पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावे और भारत के महाशक्ति बना दिए जाने की शेरखियांए सब प्रचार की प्राथमिकताओं में पीछे छूट गए हैं। इस तरहए चुनाव के तीसरे चरण की ओर बढ़ते हुएए मोदी की भाजपा कुल मिलाकर बचाव की मुद्रा अपनाने पर



विरासत कर पर विवाद को खींचने का कोई आधार नहीं

अंजन रॉय

यह प्रयास सार्थक नहीं थाए क्योंकि राजस्व अर्जन संपत्ति शुल्क के प्रशासन के अनुरूप नहीं था। इस देश मेंए संपत्ति शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिएए बड़े जमीन जायदाद के मालिकों ने संपत्ति के स्वामित्व को जारी रखने के लिए कानूनी कल्पनाएं रची थीं। ट्रस्ट पसंदीदा माध्यम थे। हिन्दू अविभाजित परिवारों की भी कुछ उपयोगिता थी। पुराने परिवारों में कुलदेवता के नाम पर ट्रस्ट बनाना भी एक व्यापक प्रथा थी।

विरासत कर को फ़िर से लागू करने का विवाद किसी और ने नहीं बल्कि पुराने तकनीक प्रेमी सैम पित्रोदा ने उठाया थाए जिसने लोकसभा चुनाव के मौजूदा अभियान में विपक्षी कांग्रेस को एक बड़ी दुविधा में डाल दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा चुनावी भाषणों में जो हंगामा मचाया हैए वह ग़लत हैए क्योंकि यह कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा नहीं है और सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं हैं। सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में अपने शुरुआती वर्षों में एक विशिष्ट

मौलिक भूमिका निभायी थी। उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण के लिए पांच मिशन मोड का विचार रखा थाए जिनमें से टेलीकॉम मिशन ने परिवर्तन एजेंट के रूप में काम किया था।

पित्रोदा ने सी.डॉट ;टेलीमैटिक्स विकास केंद्रड्ड की स्थापना की थीए जिसने देश के दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू कीं। उन शुरुआती दिनों मेंए सी.डॉट ने भारतीय परिस्थितियों के लिए विशिष्ट दूरसंचार अनुप्रयोगों पर कुछ मौलिक शोध किये थे जो विशिष्ट रूप से प्रासंगिक थे।

दूरसंचार क्षेत्रों के बाद के उदारीकरण के तरह दूरसंचार सेवाओं पर दूरसंचार मंत्रालय के एकाधिकार को खत्म करने से देश में दूरसंचार क्रांति को बढ़ावा मिला। दूरसंचार क्षेत्र को खोले बिना अगली सबसे अच्छी चीज़ए आईटी क्रांति और भारत का आईटी महाशक्ति के रूप में उभरनाए संभव नहीं हो सकता था।

उन दिनों से सैम के नाम से मशहूर सत्येन्द्र गोवर्धनदास पित्रोदा अपने मूल स्थान अमेरिका वापस चले गये थे।

लगभग चालीस साल पहले सैम पित्रोदा की इन शुरुआती चमक ने अपना काम किया है और अब सैम उस पुरानी प्रमुखता को फ़िर से हासिल करना चाह रहे हैंए लेकिन पुराने विचारों के साथ।

आज सैम पित्रोदा को कुछ ऐसे विचारों के लिए हल्के में खारिज करना अनुचित होगा जो शायद देश की वर्तमान आकांक्षओं से मेल नहीं खाते। वह केवल उस विचार को आगे बढ़ा रहे थे जिसे राहुल गांधी ने देश में आय असमानता के बारे में अपने चुनावी भाषणों के दौरान उठाया था। यदि व्यापक असमानता है तो तुरंत इसकी जड़ों पर हमला क्यों न किया जाये।

लेकिन ऐसा विचार आज की युगचेतना के विरुड्ड है। विरासत करए या जिसे अक्सर मृत्यु दिवस के रूप में जाना जाता हैए ऐसा ही एक है।

मरणासन्न स्थैतिक दुनिया मेंए जहां खेल हमेशा रमें जीतता हैए पुन हारते होश जैसा होता हैए ऐसे विचारों के लिए कुछ अपील है। गतिशील रूप से बढ़ते परिदृश्य मेंए जहां नये अवसर उभर रहे हैंए जहां खेल हमेशा शजीत.जीतश् समाधान का होता हैए ऐसे विचार

खिड़की से बाहर चले जाते हैं। अंतर्निहित कर की अवधारणा राज्य के लिए आकर्षक है क्योंकि इससे उसे व्यक्तियों की संचित बचत से लाभ मिलता है। लेकिन यह बचतकर्ताओं और निवेशकों के लिए हतोत्साहित का काम करता है। वर्तमान समय के स्टार्ट.अप गुरुओं और वर्तमान समय के सफल प्रौद्योगिकी सम्राटों पर विचार करें। मृत्यु कर्तव्य पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगीघ् ऐसे उदाहरण हैं जब मृत्यु कर्तव्य ने बहुत अच्छी तरह से काम नहीं किया है।

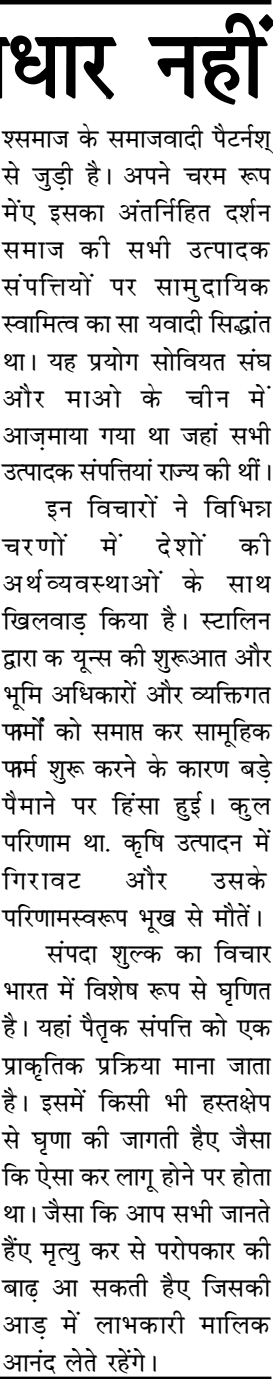
ब्रिटेन में विरासत कर या संपत्ति शुल्क था। परिणामस्वरूपए पारंपरिक संपत्तियों का कोई भी मालिक किसी वंशज की मृत्यु के बाद अपनी हिस्सेदारी बरकरार नहीं रख सका। क्रमिक चरणों में ये बचतें गायब हो गयीं। दिवालिया संपत्ति मालिकों को बचाने के लिएए ब्रिटेन को पुराने परिवारों से संपत्ति लेने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना करनी पड़ी। वे विरासत कर का भुगतान करने के बाद सक्षम नहीं हैं।

ऐसी कानूनी कल्पनाओं को प्रोत्साहित करने के बजायए वंशजों के लिए संपत्ति छोड़ देना कहीं बेहतर है। किसी भी दर परए ईमानदारी से कहें तोए बड़ी संपत्ति के लिए वंशज अगली दो पीढ़ियों में संचित संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। इसका सामाजिक रूप से लाभकारी प्रभाव पड़ता हैए जहां तक पैसा और संपत्ति लॉक होने के बजाय प्रसारित होती रहती है विरासत कर की अवधारणा

मजबूर होती नजर आ रही है।

यह उसके खुली सांप्रदायिक दुहाई का सहारा लेने के बावजूद है। उसके दुर्भाग्य से बचाव की यह मुद्रा भी काम आती नजर नहीं आ रही है। बेशकए अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ते हुएए उसने सीधे आरएसएस को भी प्रत्यक्ष रूप से मैदान में उतरने के लिए तैयार कर लिया है और स्वयं आरएसएस सरसंघचालक ने एक बयान जारी करए इसका ऐलान किया है कि आरएसएस के खिलाफ यह झूठा प्रचार हो रहा है कि वह आरक्षण के खिलाफ हैय आरएसएस हमेशा से संविधान.प्रदत्त आरक्षण के पक्ष में रहा है ;जो कि सफेद झूठ हैड्ड और रहेगाए जब तक कि आरक्षण की जरूरत रहती है।

लेकिनए ये सफ़इयां भी बहुत असर करती नजर नहीं आ रही हैं। दूसरी ओरए मोदी स ड्डुमोहन की धुंध छंटने के साथए बेकारीए महंगाई से लेकर बढ़ती तानाशाही तथा बढ़ते सामाजिक.धार्मिक विद्वेष की सच्चाइयांए आम जनता की नजरों में ज्यादा से ज्यादा चुभ रही हैं और इसे बढ़ते पैमाने पर लोग स्वर भी दे रहे हैं। इन हालात मेंए तीसरे चरण में संघ.भाजपा की बदली हुई चुनावी कार्यनीति की विफलता सामने आने के बादए चुनाव के बीचौ.बीच संघ.भाजपा की घबराहट क्या रूप लेती हैए अभी कल्पना करना मुश्किल है। सांप्रदायिक ध्वीकरण की चालें काम नहीं कर रही हैं। साहेब घबराया हुआ है। यह दिलचस्प समय है। यह खतरनाक समय भी है।





सहायक आचार्य नियुक्ति से सीटेट और दूसरे राज्यों ड्रॉप आउट बच्चों की जांच से टेट उज्जीर्ण अभ्यर्थी बाहर, जेटेट ही मान्य के लिए बनाई गई स्पेशल टीम

रांची २१/११ (संवाददाता): राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होनेवाली नियुक्ति से सीटेट (केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) तथा दूसरे पड़ोसी राज्यों से टेट उज्जीर्ण अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उज्जीर्ण अभ्यर्थी ही इस पद पर नियुक्त हो सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीटेट तथा दूसरे राज्यों से टेट उज्जीर्ण वैसे 53,60२4 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं, जिन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के



आदेश के आलोक में आवेदन का अवसर प्रदान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के उक्त आदेश निरस्त होने के बाद आयोग ने यह

निर्णय किया। आयोग ने मंगलवार को सूचना जारी कर कहा कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 से संबंधित याचिका संज्ञा एसएलपीसी 4194/2024 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश के आलोक में परीक्षा संबंधी 15 फरवरी 2024 को जारी संशोधित परीक्षा विवरणिका को रद्द किया जाता है। साथ ही 22 अक्टूबर 2023 के बाद प्राप्त

सभी आवेदनों को रद्द किया जाता है। दरअसल, आयोग द्वारा 15 फरवरी 2024 को जारी संशोधित विवरणिका के तहत इन पदों पर होनेवाली नियुक्ति में उच्च न्यायालय के आदेश पर झारखंड के रहनेवाले वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सज्जित होने की अनुमति प्रदान की गई थी, जो सीटेट या पड़ोसी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा उज्जीर्ण थे, लेकिन उसमें यह शर्त रखी गई थी कि संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर एवं पहले उपलब्ध अवसर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उज्जीर्ण होना अनिवार्य होगा।

लेकिन बाद में जेटेट उज्जीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देने पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 2015 को पारित आदेश के आलोक में 22 अक्टूबर 2023 के बाद भरे गए सभी आवेदनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। लेकिन कई अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित करने की स्थिति में अद्यतन आवेदन को वैध मानते हुए इस तिथि के पूर्व भरे गए आवेदनों को आयोग द्वारा पूर्व में रद्द किया गया था। अब एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को आयोग द्वारा रद्द घोषित किया गया था, वैसे अभ्यर्थियों के 22 अक्टूबर 2023 के पूर्व भरे गए आवेदन को पुनर्बहाल कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की संज्ञा 1,196 है। उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर परीक्षा संबंधी शेष कार्रवाई की जाएगी।

रांची २१/११ (संवाददाता): सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चे वापस लौटें या नहीं, इसकी जांच होगी। इसे लेकर सभी 24 जिलों के लिए अलग-अलग गठित राज्य स्तरीय टीम बुधवार से स्कूलों का निरीक्षण करेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में इसे लेकर राज्य स्तरीय टीम को प्रशिक्षण दिया गया। इस क्रम में राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने 61 सदस्यीय टीम को कई आवश्यक निर्देश भी दिए।

राज्य स्तरीय टीम को संबोधित करते हुए निदेशक ने सुबह नाश्ते से पहले निरीक्षण का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण स्कूलों का समय सुबह साढ़े ग्यारह बजे तक ही है। ऐसे में बच्चों से बात कर स्कूल की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए सभी टीमों अहले सुबह ही फील्ड में भ्रमण के लिए निकल जाएं। कहा कि दो-तीन वर्ष में लगातार जिस स्कूल में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का आंकड़ा नहीं सुधर रहा है, वहां अनिवार्य रूप से जाएं।



स्कूलों में शिशु पंजी सर्वे की गहनता से जांच करे। उन्होंने टेबल वर्क नहीं करने की चेतावनी भी दी। निदेशक ने कहा कि बीआरपी और सीआरपी अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट दें। उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने टीम के सदस्यों को भ्रमण के दौरान आचरण में गंभीरता लाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने जीरो ड्रॉप आउट की जमीनी हकीकत जानने का निर्देश दिया। ज्कहा कि स्कूल का दावा सही है, तो उसे प्रोत्साहित किया जाएगा और दावा भ्रामक पाए जाने पर स्कूल

के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में 75 प्रतिशत उपस्थित है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बताते चलें कि स्कूलों का निरीक्षण 20 मई तक होगा। टीम को 27 मई तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।

निदेशक ने गिरिडीह के बेलको हाई स्कूल, गोपालडीह द्वारा स्टूडेंट माइग्रेशन का भ्रामक डाटा उपलब्ध कराने पर उसकी जांच का आदेश दिया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्कूल ने यू-डायस पोर्टल पर स्टूडेंट माइग्रेशन के संबंध में अताकिंक और भ्रामक डाटा अपलोड किया है।

नो व्हीकल जोन का प्रयास बेहतर, बकरी बाजार में अस्थाई पार्किंग से 100 वर्ष पुराना बाजार बचेगा



रांची २१/११ (संवाददाता): अपर बाजार स्थित बकरी बाजार की चार एकड़ जमीन पर नगर निगम का कबाड़ भरा है। बकरी बाजार मैदान में एक ओर कंडम सिटी बसेए टैंकर और अन्य वाहन भरे हैं तो दूसरी ओर शव जलाने के लिए लाए गए जलावन को डंप कर रखा गया है।

यहां खड़े वाहनों के पार्ट्स दिन व दिन चोरी हो रहे हैं लेकिन निगम इसे कबाड़ घोषित कर नहीं बेच रहा है। इस वजह से पूरा मैदान भरा है। इस कबाड़ को बकरी बाजार से हटा दिया जाए तो यहां अस्थाई वाहन पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी। इससे पूरे अपर बाजार क्षेत्र में वाहन लगाने की समस्या दूर हो जाएगी। व्यापारियों के साथ ग्राहकों को भी काफी फायदा होगा। अपर बाजार के व्यापारी भी यही चाहते हैं। गुरुवार को दीनबंधु लेन मर्चेट एसोसिएशन और चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने लोहिया धर्मशाला में पत्रकारों

से बात करते हुए सोनार पट्टी व रंगरेज गली को नो व्हीकल जोन घोषित करने के लिए निगम प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस का आभार जताया।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मोर व सचिव राजेश कौशिक ने कहा कि ग्राहकों की सुविधा के लिए वेंडर मार्केट का बेसमेंट ए यूनियर्सिटी के बगल में पेपर मार्केट के सामने ए सेवा सदन हॉस्पिटल के सामने वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बकरी बाजार व बाजारटांड में भी अस्थायी पार्किंग बन जाए तो व्यापारियों व ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मोर ने कहा कि अपर बाजार क्षेत्र के दुकानदारों की सुविधा के लिए वेंडर मार्केट से अपर बाजार तक ई.रिज्शा का परिचालन होगा। व्यापारी व ग्राहक मार्केट में अपने वाहन पार्क कर ई.रिज्शा से बाजार आ जा सकते हैं। कुछ व्यापारियों द्वारा ग्राहकों से पार्किंग शुल्क के रूप में भुगतान किए गए पैसे दिए जाएंगे।



आज का राशिफल

मे़ष – आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ विशेष रहेंगी। मन में द्विधा रहने से ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार न करने की गणेशजी की सलाह है।

वृषभ – गणेशजी कहते हैं कि व्यापार में वृद्धि होने के साथ व्यापार के सज्जंध में सौदे लाभदायक साबित होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव मिलेगा।

मिथुन – शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। नौकरी – व्यवसाय में आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कर्क – गणेशजी कहते हैं कि आज आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। तथा विदेश से अच्छे समाचार आएँगे।

सिंह – आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। निषेधात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर न ले जाए, उसका ध्यान रखने के लिए गणेशजी कहते हैं।

कन्या – गणेशजी की कृपा से दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ज्य़ाति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी।

तुला – गणेशजी कहते हैं कि सामान्ज रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति के भी तबीयत में सुधार होगा। घर में सुख- शांति के वातावरण में आप समय व्यतीत करेंगे। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा।

वृश्चिक – आज यात्रा प्रवास का आयोजन न करने की सलाह गणेशजी देते हैं। स्वास्थ्य के सज्जंध में चिंतित रहेंगे। संतानों के सज्जंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें।

धनु – गणेशजी कहते हैं कि आज आपको अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव खड़े होने की संभावना है। मन में उठनेवाली द्विधाओं से आप मानसिक उचाट अनुभव करेंगे।

मकर – आज आप रणनीति में शत्रुओं को परास्त करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। आप हरेक कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। व्यापार- धंधे में लाभ होगा।

कुंभ – गणेशजी बताते हैं कि मन में द्विधाएँ खड़ी होने से आप कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच सकेंगे। महज्ज्वपूर्ण निर्णय न लें। वाणी पर संयम नहीं रहनेसे पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है।

मीन – आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। नए कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। धार्मिक मांगलिक प्रसंगों में जाएँगे।

खेलगांव हाउसिंग में छत से गिरकर सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत, बिहार के रहने वाले थे दिवाकर सिंह

रांची २१/११ (संवाददाता): खेलगांव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर सिंह का शव पुलिस ने सुबह पार्किंग एरिया से बरामद किया। पुलिस आत्महत्या एवं दुर्घटना दोनों एंगल से जांच कर रही है। वे 47 वर्ष के थे और मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे। अपनी बेटी व पत्नी के साथ खेलगांव में रह रहे थे। वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले थे। उनकी पोस्टिंग दीपाटोली ,रांचीड्ड स्थित सेना के

मुज्यालय में थी। खेलगांव हाउसिंग सोसायटी में शव पड़े होने की सूचना पर मंगलवार की सुबह पुलिस पहुंची। पुलिस ने पाया कि दिवाकर सिंह की मौत हो चुकी है। शव को सबसे पहले गार्ड ने देखा। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी ने पुलिस को बयान दिया है कि दिवाकर शाम से छत पर बैठे हुए थे। वह अजसर छत पर घंटों बैठते थे। सोमवार की रात पत्नी ने दिवाकर को कई बार फोन कर घर के अंदर आने के लिए कहा था। वे बार.बार यही कह रहे

थे कि कुछ देर में आते हैं। इसके बाद पत्नी अपनी बेटी के साथ सो गई। सुबह में पत्नी को पता चला कि छत से गिरने से दिवाकर की मौत हो गई है। खेलगांव थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया.शुरुआती जांच में पता चला है कि पैसे को लेकर दिवाकर परेशान थे। हालांकि घरेलू और कार्यालय की भी परेशानी हो सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर सिंह की पत्नी ने पुलिस को बयान दिया है कि उनका इलाज चल रहा था। वह मानसिक रूप से

बीमार चल रहे थे। दिवाकर को दवा दी जा रही थी। तीन माह से ज्यादा परेशान चल रहे थे। वे कार्यालय में आर्मी सफ्टाई कोर का काम देखते थे। पिछले एक साल से अध्ययन के लिए अवकाश पर थे। दिवाकर किस बात को लेकर परेशान थे? इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। दिवाकर सिंह का बेटा दिल्ली में रहकर एमबीए की तैयारी कर रहा है। उसे घटना की जानकारी दे दी गई है। उनकी एक बेटी है जो रांची में रहकर पढ़ाई करती है।

रोड़ों खर्च करने के बाद भी ज्यों रुका खरकई डैम का काम, हाई कोर्ट ने सचिव से मांगा जवाब

रांची २१/११ (संवाददाता): झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में सरायकेला में खरकई डैम निर्माण पर छह हजार करोड़ से अधिक खर्च होने के बाद प्रोजेक्ट बंद करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 6100 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है।

प्रोजेक्ट के लिए टेंडर करने से पहले राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर बनाई होगी। ज़्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में राज्य सरकार ने जमीन

अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों के आंदोलन को लेकर किसी प्रकार का विचार नहीं किया था। अदालत ने कहा कि अगर यही स्थिति है तो अदालत मामले में सीबीआई को प्रतिवादी बनाकर जांच करवा देती है। जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है।

अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि 6100 करोड़ खर्च होने के बाद खरकई डैम प्रोजेक्ट ज्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद ज़्या काम बंद रहेगा। अगर वहां ग्रामीण आंदोलनरत हैं तो उसके लिए

आप ज़्या कर रहे हैं। खरकई डैम प्रोजेक्ट को लेकर अंतिम रूप से सरकार ने ज़्या निर्णय लिया है।

अदालत इन बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की गई है। मामले में जल संसाधन विभाग की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया है कि जमीन अधिग्रहण पर स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण खरकई डैम प्रोजेक्ट बंद है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि छह हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने के बाद खरकई डैम प्रोजेक्ट

को वर्ष 2020 में प्रोजेक्ट को ज्यों बंद कर दिया गया था। इस संबंध में संतोष कुमार सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1978 में एकीकृत बिहार ए ओडिशा एवं बंगाल सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसी के तहत खरकई डैम का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बिना कारण के बंद कर दिया गया। इस डैम के लिए जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है और प्रभावित विस्थापितों को बसाने के लिए नया जगह भी चिह्नित किया गया। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए।



ओडिशा को 2036 तक समृद्ध राज्य बनाना प्राथमिकता, मोहन चरण माझी बोले-जमीन पर नजर आने लगे काम

भुवनेश्वर २१/११ (संवाददाता): ओडिशा को महाप्रभु जगन्नाथ ने वह सब कुछ दिया है जो किसी भी विकसित राज्य के लिए जरूरी है। प्रदेश में 480 किलोमीटर लंबा विशालकाय समुद्री तट है। प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। कुशल मानव संसाधन के साथ पोर्ट, रेल एवं सड़क मार्ग की बेहतर सुविधा है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो देश के चारों धर्मों में से एक जगन्नाथ धाम यहां है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अब प्रदेश में डबल इंजन सरकार है। जिसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है और जमीन पर विकास के काम नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री के पूर्वोच्चर से उदय के सपने को हमारी सरकार ने मिशन के रूप में लेते हुए विकास के कार्यों को गति दी है। यह बातें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहीं।



मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा 2036 में भाषा आधारित राज्य गठन की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। हमारा लक्ष्य तब तक ओडिशा को एक समृद्ध राज्य बनाना है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि भारत के विकसित देश बनाने में ओडिशा का बड़ा योगदान हो। यह तभी संभव है जब

ओडिशा हर क्षेत्र में समृद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि तब तक ओडिशा उस मुकाम को हासिल कर ले कि हम देश के दूसरे राज्यों को भी प्रगति की राह दिखा सकें। हमारे पास इसके लिए मिनरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधनों में लौह अयस्क, मैंगनीज, बाज्साइट व क्रोमाइट प्रचुर मात्रा में हैं। आज ओडिशा रेवन्यू में सरप्लस है। हमारी जीडीपी 7.2 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का फायदा ना सिर्फ ओडिशा के नागरिकों को मिलने लगा बल्कि निवेश की भी राहें खुलीं।

निवेशकों के लिए ओडिशा अब पहली पसंद बन गया है। देश की नामी-गिरामी कंपनियां ओडिशा में निवेश करने की इच्छा जाहिर कर रही हैं। दिल्ली एवं मुंबई में हुए निवेशक सम्मेलन में ओडिशा

सरकार के साथ कई कंपनियों ने समझौते किए। कई कंपनियों के साथ सार्थक वार्ता हुई। उत्कर्ष ओडिशा सज्मेलन में खुद प्रधानमंत्री ने देश एवं दुनिया भर के निवेशकों को मोदी की गारंटी दी है। इसका लाभ भी हमें मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2025 तक हम अपनी पहली सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। आरएंडडी कंपनी के सहयोग से स्थापित यह इकाई इंपो वैली में 2,000 वर्ग फुट की सुविधा पर काम करेगी। हमारा लक्ष्य मेक इन ओडिशा पहल के तहत ओडिशा को आईटी और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कोरापुट और केंदुझर में डेटा सेंटर स्थापित करने पर काम चल रहा है ताकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। पुरी में भी केबल लैंडिंग स्टेशन बनने की तैयारी है।

एसएमएस-1 द्वारा हीट का अब तक का सबसे लंबे क्रम के साथ नया रिकॉर्ड दर्ज



राउरकेला २१/११ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के स्टील मेल्टिंग शांप-1 (एसएमएस-1) ने 30 अप्रैल, 2025 को कंटीन्यूअस कार्स्टिंग मशीन-1डु में 31 हीट का अब तक का सबसे लंबा क्रम हासिल करके एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। यह 1 जुलाई, 2023 को स्थापित 30 हीट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर मुख्य महाप्रबंधक (एसएमएस-1), श्री बी सुनील कार्था के सक्रिय

मार्गदर्शन में महाप्रबंधक (ऑपरेशन), श्री नीलमणि महापात्र के नेतृत्व में एसएमएस-1 टीम द्वारा प्रदर्शित अनोखे परिचालन प्रभावशीलता का परिणाम था, साथ ही पीपीसी, ज़्लास्ट फर्नेस, क्रेन अनुरक्षण और यातायात और कच्चे माल विभाग सहित प्रमुख विभागों से निर्बाध समन्वय और समर्थन का नतीजा भी था। 1050 मिमी चौड़ी x 210 मिमी मोटी स्टील स्लैब की ढलाई 29 अप्रैल को सुबह 6.50 बजे शुरू हुई और 30 अप्रैल को सुबह 10:15 बजे समाप्त हुई, जिसमें

कुल 27 घंटे और 20 मिनट का समय लगा। इस अवधि के दौरान, 1.25 किलोमीटर की ढलाई की गई, जिससे 2,128 टन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील स्लैब का उत्पादन हुआ। 1960 के दशक की शुरुआत में कमीशन किया गया, एसएमएस-1 भारत में एलडी स्टील निर्माण में अग्रणी था। इस इकाई ने लगातार विशेष ग्रेड स्टील के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं में योगदान दिया है।

ओडिशा हाई कोर्ट का आदेश, जमानत पर छूटने के बाद 2 महीने तक थाना परिसर की सफाई करेगा आरोपी

भुवनेश्वर २१/११ (संवाददाता): उच्च न्यायालय ने ऐसे समय में एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया है, जब आरोपी को सुधारने और संस्कार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उच्च न्यायालय ने जेल में बंद एक आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है और थाना परिसर की सफाई और 100 पौधे लगाने जैसी शर्तें रखी हैं। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद याचिकाकर्ता दो माह तक चंदका थाना परिसर की सफाई का काम करेंगे।



सके। इसके साथ ही आम, नीम, इमली जैसे 100 पौधे आवेदक द्वारा अपने गांव के पास के क्षेत्र में लगाए जाएंगे। आगामी मानसून में आवेदक इन वृक्षों को सरकारी भूमि/सामुदायिक/निजी भूमि पर लगाएगा। यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो राजस्व अधिकारी पौधे लगाने के लिए आवश्यक

भूमि की पहचान करने में सहायता करेंगे। जिला नर्सरी/डीएफओ पौधे उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।

आवेदक ने पौधा लगाया है या नहीं इसकी निगरानी संबंधित पुलिस स्टेशन के आईआईसी द्वारा स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके की

जाएगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक हलफनामा दायर करेगा, ताकि पौधे लगाने के साथ-साथ दो साल तक इन पौधों की देखभाल की जा सके। इसी तरह, आवेदक प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच स्थानीय पुलिस

स्टेशन में उपस्थित होगा। उच्च न्यायालय ने शर्त लगाई है कि वह जमानत पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं होगा। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर याचिकाकर्ता की जमानत रद्द कर दी जाएगी। न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्रही की खंडपीठ ने बिट्टु की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। मामले के विवरण से पता चला है कि याचिकाकर्ता को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के संबंध में इंपोसिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

भुवनेश्वर से अबू धाबी के लिए शुरू होगी सीधी विमान सेवा, जल्द होगा तारीखों का एलान

भुवनेश्वर २१/११ (संवाददाता): भुवनेश्वर से अबूधाबी के लिए जून 2025 से सीधी उड़ानें होंगी। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के लिए एक ऐतिहासिक विमानन पहल करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इंटरनेट मीडिया एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ओडिशा को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पर्यटन,



व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे विकसित ओडिशा के निर्माण के काम को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि टेंपल सिटी से ग्लोबल गेटवे, इस ऐतिहासिक विमानन मिशन को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद। जानकारी के अनुसार इंडिगो विमानन कंपनी सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ानें

संचालित करेगी। दोनों प्रमुख शहरों के बीच उड़ानें शुरू करने की सही तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। राज्य सरकार ने उम्मीद जताई कि इस पहल के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली ओडिशा की कनेक्टिविटी में सुधार और इसे वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के उभरते केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाएगी।

पूर्व मंत्री नव दास हत्या मामले में नया मोड़, क्राइम ब्रांच ने फिर शुरू की जांच

भुवनेश्वर २१/११ (संवाददाता): ओडिशा के पूर्व मंत्री नव दास की हत्या का मामला अब एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामले के चर्चा में आने का कारण है क्राइम ब्रांच की जांच। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूर्व मंत्री दास की पूर्व विधायक बेटी दीपाली दास एवं बेटे विशाल दास को नोटिस जारी किया है। क्योंकि उनकी आपर्जि के बाद ही क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर मामले की जांच शुरू की है। ऐसे में मामले में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पूर्व विधायक दीपाली दास और उनके भाई विशाल को नोटिस जारी किया है। उन्हें मार्च के पहले सप्ताह में किसी दिन अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया

है। अगर उन्हें क्राइम ब्रांच की जांच को लेकर कुछ कहना है या कोई आपर्जि है तो वे उस दिन इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी विनयतोष मिश्रा ने कहा है कि नव दास की हत्या की जांच जारी है। नए सिरे से जांच दीपाली की पिछली याचिका के बाद शुरू की गई है। जिन्होंने राज्य सरकार से जांच को केंद्रीय जांच ज्यूरी को स्थानांतरित करने का आग्रह किया था इससे पहले दीपाली दास ने राज्य सरकार से इस मामले की गहन जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया था। मार्च के पहले सप्ताह में क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होकर अपनी आपर्जि दर्ज

कराएंगी पूर्व विधायिका। भाजपा के कई नेताओं ने पहले आरोप लगाया था कि तत्कालीन बीजद सरकार ने इस मामले में बड़ी साजिश रची और नव दास की हत्या की गई। अब हत्या के आरोपित गोपाल दास के वकील ने आरोप लगाया है कि क्राइम ब्रांच की जांच में कई खामियां हैं। इसके बाद इस हत्याकांड को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई। भाजपा के कई नेताओं ने अपने मूल आरोपों को दोहराया। इस बीच दीपाली ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच कराने को भी कहा। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और कह रहे हैं कि अगर दीपाली दास लिखित में आवेदन करती हैं तो सरकार सीबीआई जांच कराएगी।

राउरकेला २१/११ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के रिफ्रेजट्रीज इंजीनियरिंग (सेवा) विभाग ने विज्ञीय वर्ष 2024-25 में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है, परिचालन दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और तकनीकी नवाचार में कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, जिससे संयंत्र को काफी बचत हुई है। एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में, कंटीन्यूअस कार्स्टिंग मशीन-1 (सीसी एम-1) स्टील लैंडल ने 88.0 हीट्स का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक औसत जीवनचक्र प्राप्त किया, जो विज्ञ वर्ष 2023-24 में दर्ज किए गए 84.90 हीट्स के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर



गया। यह सुधार गुणवत्ता वृद्धि, प्रक्रिया अनुकूलन और सावधानीपूर्वक रखरखाव प्रथाओं पर विभाग के निरंतर प्रयास का उदाहरण है। इसी तरह, आरएच-ओबी इकाई ने

143.56 हीट्स पर अपना उच्चतम वार्षिक औसत जीवनचक्र दर्ज किया, जो 142.10 हीट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। लाइनिंग प्रदर्शन में लगातार

सुधार ने डाउनटाइम को कम करने और उत्पादकता में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 6.65 किलोग्राम प्रति टन ज़रूड स्टील

(टीसीएस) पर अब तक की सबसे कम विशिष्ट रिफ्रेजट्री खपत रही है। यह मील का पत्थर न केवल बेहतर रिफ्रेजट्री प्रबंधन को दर्शाता है बल्कि लागत में कमी और टिकाऊ संचालन में एक कदम आगे का संकेत भी देता है। आरएसपी में प्रथम तकनीकी उपयोग के तौर पर विभाग ने इन्सुलेंटिंग पंपेबल कार्टेबल का उपयोग करके ज़्लास्ट फर्नेस-5 स्टोव डोम क्षेत्र के सफल ग्राउंटिंग किया है। इस अभिनव दृष्टिकोण से शेल तापमान में काफी कमी आई है। डु टीम भविष्य की सफलताओं का मार्ग सशक्त करते हुए अधिक दक्षता और लागत प्रभावशीलता की दिशा में प्रयासरत है।